रही है और यदि हां, तो सरकार ने विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि जन्य उत्पादों का निर्यात करने के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार हरियाणा के किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में कृषि-उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को ध्यान में रखकर उद्योग लगाने पर विचार कर रही है; और इस संबंध में चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) : सरकार ने देश से औद्योगिक क्षेत्रों से प्र-संस्कृत मदों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति वातावरण बनाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं --(1) उदार विनिमय दर प्रबंधन योजना की सुविधा प्रदान करना (2) आयात-निर्यात नीति में कृषि क्रिया-कलाप को विनिर्माण क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करना (3) कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात पर कुछ खास शर्तों के अध्यधीन अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण समाप्त करना (4) मसालों पर लगने वाले उपकर की दरें दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से सुव्यवस्थित कर दी गई हैं और वर्ष 1992-93 के लिए काली मिर्च के निर्यात पर उपकर से छूट दी गई है। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, विभिन बोर्ड तथा प्राधिकरण विदेशों में प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में हिस्सा लेते हैं ताकि वे भारतीय दाल का निर्यात संवर्धन करने के उद्देश्य से अन्य देशों के आयातकों के साथ परस्पर बातचीत कर सकें। इसके अलावा, बोर्ड/प्राधिकरण उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता में सुधार लाने में उत्पादकों की सहायता करते हैं और निर्यात प्रयासों में सुधार लाने हेतु भारतीय उत्पादों के ब्राण्ड नामों के संवर्धन में सहायता प्रदान करते हैं। किन्तु, सरकार की नीति यह है कि कृषि जन्य वस्तुओं का निर्यात संवर्धन इस तरह से किया जाए कि आम जनता के उपभोग की मदों की घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

Export of Sea Foods

1647. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what steps are taken by Government to promote further development of sea-foods and to export the same to continental market from Porbandar coastal area;

(b) whether Government are considering any time bound action plan to export sea-foods; and

(c) if so, what facilities and assistance Government propose to provide to promote development and export of sea food ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED) : (a) Main items of seafood exported from Porbandar coastal area to continental markets are frozen shrimp. frozen/fresh fish, frozen cephalopods and frozen whole cooked lobsters. There are presently 3 seafood processing units in Porbandar. MPEDA has assisted 2 of these processing plants for setting up IQF units. Since this could mean higher value addition and therefore better price.

(b) MPEDA regularly implements Annual Plans for encouraging export of Seafood.

(c) MPEDA implements schemes for increasing export production through both capture and culture sectors, as well for modernisation of sea-food industry and market promotion.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात

1648. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वस्तुओं का आयात किया है जिन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित किया जा रहा है;